REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 8 | MAY - 2025

"सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का अवधारणात्मक अध्ययन"

लवकुश हरिजन[1], डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.).
[2]सहायक प्राध्यापक भूगोल, इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.).

सारांश–

सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु व सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूरों और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ऋण, अनुदान और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। सतना जिले जैसे पिछड़े क्षेत्र में इस योजना के तहत ग्रामीण आय और आजीविका में सुधार हुआ है, किंतु योजना के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, प्रशासनिक जटिलताएँ, और निगरानी की कमी जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं। फिर भी, यदि योजना को प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता, और स्थानीय सहभागिता के साथ लागू किया जाए, तो यह जिले के ग्रामीण विकास में एक सशक्त उपकरण सिद्ध हो सकता है। ग्रामीण विकास जहां एक ओर कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर आश्रित है वहीं इन कार्यों के लिए आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता और ग्रामीण रोजगार भी आवश्यक है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना रही है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उनमूलन, रोजगार सृजन, और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। इस योजना का क्रियान्वयन सतना जिले जैसे अर्द्ध–आदिवासी और विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है।

मुख्य शब्द – सतना जिला, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण गरीबी, रोजगार सृजन, योजना क्रियान्वयन, स्थानीय सहभागिता, सामाजिक–आर्थिक विकास।

प्रस्तावना

एकीकृत ग्रामीण विकास एवं बहुआयामी अवधारणा है जिसका अध्ययन मुख्यता तथ्यों पर आधारित है। संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास का अभिप्राय विविध कार्यक्रमों जैसे कृषि पशुपालन ग्रामीण हस्तशिल्प कला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव इत्यादि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। व्यापक दृष्टि से ग्रामीण विकास का आर्थिक ग्रामीणजनों के जीवन में गुणात्मक उन्नति के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना। बसन्त देशाई (1988) ने भी ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए किया था ''ग्रामीण विकास का अभिप्राय है, जिसके द्वारा गाँव जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता हेतु क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक, आर्थिक विकास किया जाता है और उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह सुस्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास सिर्फ कृषि व्यवस्था एवं कृषि उत्पादन के साधन एवं सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियाओं, ग्रामीण विकास की परिधि में

सम्मिलित है। ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाने में सामुदायिक विकास परियोजना की विशेष भूमिका रही है। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गांव के जनमानस को प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास करना, सहकारी ढंग से काम करने की आदत उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि करना। सामुदायिक विकास योजनाओं के इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीणों में शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, गृह निर्माण, वृक्षारोपण, भूमि सुधार सड़क निर्माण आदि कार्यों पर जोर दिया गया है। सामुदायिक विकास योजनाएं एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जो ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं भौतिक उत्थान को प्रेरित करता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू सामुदायिक विकास योजनाओं को भारत की जगमगाती जीवन से परिपूर्ण एक गतिमान रोसनियां मानते हैं। जिनसे शक्ति, आशा एवं उत्साह की किरणें फूटती है।

ग्रामीणों के लिए विकेन्द्रित प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में पंचायतीराज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। पंचायतें सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद होती है। भारत के गांवों के विकास के लिए प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायते कार्य करती आ रही है। पंचायते गांवों की आर्थिक, न्यायायिक एवं सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर ग्रामीण विकास के अवसर को बढ़ाती है। पंचायतें ग्रामीणों के विकास के लिए सड़क निर्माण, स्वच्छता पेयजल, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता शिक्षा, कुटीर उद्योग इत्यादि विकास को निष्पादित करती है।

शोध अध्ययन में मध्यप्रदेश के सतना जिले को शोध बिन्दु मानकर अध्ययन किया गया है। सतना जिला मध्यप्रदेश में विद्यमान है जिसका अक्षांशीय विस्तार 23.58 डिग्री से 25.12 अंश उत्तरी अक्षांश और 80.20–81.23 अंश पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी समुद्रतल से ऊंचाई 317 मीटर है। जिले में 11 तहसीले हैं जो क्रमशः सोहावल (सतना) रामपुर बाघेलान, नागौद, मैहर, उचेहरा, रामनगर, अमरपाटन, बिरसिंहपुर, कोटर, मझिगवां और रघुराजनगर। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7424 वर्ग किमी. है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबाद ग्राम 1816 है और ग्राम पंचायत 704 और कुल जनसंख्या 22,28,935 है।

ग्रामीण विकास को सूक्ष्म योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा देने के महत्व को तब परिलक्षित तब परिलक्षित हुआ था। जब यह सुस्पष्ट हो गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की समस्याओं का निराकरण करने में व्यापक उद्योग तंत्रीय मार्ग प्रभावहीन हो चुके थे। तत्पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि समन्वित विकास की समस्या के लिए एक बहुआयामी उपागम कीी आवश्यकता है तथा साथ ही साथ कृषि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना भी आवश्यक है, जिससे की ग्रामीण आर्थिकी में अमूल चूक ढाँचागत परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार एकीकृत ग्रामीण विकास से संबंधित विविध तथ्यों को बिन्दुवार निम्नानुसार स्पष्ट कर सकते हैं–

एकीकृत ग्रामीण विकास की अवधारणा दो तत्वों पर आधारित है। पहला कार्य सम्बन्धी, दूसरा स्थान सम्बन्धी जो स्वयं में एक दूसरे पर आधारित हैं कार्य सम्बन्धी विकास से तात्पर्य है वे सभी आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाएँ जो सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। किसी एक क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार विकास की नीति परस्पर एक दूसरे के सम्बन्धित होना चाहिए। वर्तमान समय में प्रशासकों, नियोजकों, अर्थशास्त्रियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसी बात से परेशानी है कि एकीकृत विकास नीति का क्रियान्वयन किस ढंग से किया जाय।

सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों का आपसी तारतम्य तथा उसकी सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वे किन क्षेत्रों में स्थापित अधिक सक्रिय है तथा दूसरे क्षेत्र अछूते हैं। इन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए। परिवहन के साधनों की सुलभता वहां के लोगों की आर्थिक दशा आर्थिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने का खर्च ये सभी बातें प्रमाणित करती हैं कि हमारे देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों में ये सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः जब नियोजन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाता है, तो समय विशेष का चुनाव काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है।

अतः एकीकृत ग्रामीण विकास से तात्पर्य है कि स्थान विशेष का चुनाव करते समय केवल भौगोलिक तथ्य को भी ध्यान में गया है, सम्पूर्ण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाय। उपयुक्त स्थान का चुनाव विभिन्न तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अधिवासों की समस्या को सुलझाते समय, आर्थिक तथा विभिन्न सामाजिक आधारतलों पर उपलब्ध साधनों पर ध्यान रखा जाय। किसी भी उद्योग अथवा आर्थिक

इकाई को स्थापित करते समय स्थान विशेष की उपयोगिता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अतः एकीकृत ग्रामीण विकास से तात्पर्य है कि आर्थिक तथा सामाजिक कार्यकलापों का इस प्रकार से विकेन्द्रीकरण किया जाय तथा उन्हें इस प्रकार स्थापित किया जाय कि सम्पूर्ण क्षेत्र की प्रगति हो सके। इस प्रकार विकास का ढांचा खड़ा करने से विकासशील आर्थिक नियोजन को सुदृढ़ आधार प्राप्त हो सकेगा।

शोध उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध आलेख "सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का अवधारणात्मक अध्ययन" विषय को प्रस्तुत किया गया है, उक्त शोध आलेख से संबंधित कुछ उद्देश्य निम्नांकित है–

- अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण में भौगोलिक तथ्यों की भूमिका का अध्ययन करना।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति का मूल्यांकन करना जिसमें कृषि, बाजार, वित्तीय संस्थायें, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण विकास आदि आयामों का अध्ययन करना।

उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये शोध आलेख को यथा संभव मानकों के अनुरूप पूर्ण किया गया है।

शोध विधि –

किसी भी शोध आलेख में प्रयोग में लायी जाने वाली विधि को अध्ययन को शोध विधि कहते हैं। अध्ययन की सार्थकता के लिये वैज्ञानिक पद्धति सबसे अधिक उपयोगी है। निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण की एक सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन पूर्ण तथा सत्यता व वास्तविकता के नजदीक होता है। प्रस्तुत शोध विषय के निष्कर्षों की सार्थकता की दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला गया है। सतना जिले के एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का अवधारणात्मक स्वरूप को निरूपित करने के लिये उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रहन–सहन इत्यादि गतिविधियों को आधार बनाकर सामाजार्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है जिसके आधार पर यह स्पष्ट किया जा सका है कि आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पूर्व के वर्षों की तुलना में वर्तमान में काफी परिवर्तित हुई हैं। जिसकी वजह से उनके रहन–सहन, व्यवहार इत्यादि क्रियाओं में काफी बदलाव आया है।

विश्लेषण –

सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अवधारणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जा रहा है। योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं संसाधनों का समन्वय कर विकास की प्रक्रिया को गति दी जाती है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जहाँ योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रहा है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, आधारभूत संरचना और रोजगार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक अड़चनें, संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव और स्थानीय स्तर पर सहयोग की कमी जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस हद तक इसे जमीनी स्तर पर ईमानदारी और समर्पण के साथ लागू किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अनेक पिछड़े क्षेत्रों को एकीकृत ग्रामीण विकास के माध्यम से धीरे–धीरे अस्तित्व में लाया जा सकेगा। इसके माध्यम से सतना जिले का भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या का सन्तुलन भी सतत् रूप में बना रहेगा और इनके साथ–साथ शोध क्षेत्र में सेवा केन्द्रों एवं विकास केन्द्रों का भी तेजी से विस्तार व विकास सम्भव होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के सफल क्रियान्वयन से केन्द्रीय ग्राम, सेवा केन्द्र, विकास केन्द्र, क्षेत्रीय नगर सड़क, आवागमन के साधनों व संचार साधनों द्वारा अध्ययन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों को नगरों एवं महानगरों से जोड़ा जा सकेगा। अतएव शोध क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रों के विकास का नियोजन करते समय सेवा केन्द्रों के उचित स्थानों का चयन एवं आर्थिक नियोजन की सम्भावनाओं पर विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि इस योजना के क्रियान्वयन से सतना जिले के सभी क्षेत्रों का समेकित रूप में विकास हो सके, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव होगा।

अध्ययन क्षेत्र एकीकृत ग्रामीण विकास की दृष्टि से एक सुदृढ़ जिला है और विकास हेतु विभिन्न संसाधन सुविधाएं उपलब्ध है, किन्तु राज्य के अन्य साधन सम्पन्न जिलों की तुलना में यहां उतना विकास नहीं हो पाया, जिससे यहां के जनमानस का सामान्य जीवन स्तर काफी निम्न है, जो सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को प्रदर्शित करता है। पिछले कुछ वर्षों से जिले की आवश्यकता के सभी क्षेत्र जैसे, परिवहन, संचार, निर्माण कार्य सेवाएं, सिंचाई, पर्यटन एवं पशुपालन इत्यादि क्षेत्रों में आवश्यक वृद्धि हुई है। साथ ही सामाजिक व आर्थिक कार्यों जैसे शिक्षा, आवास, मनोरंजन एवं रोजगार आदि में काफी सुधार हुआ है। परन्तु बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बहुत कम वृद्धि हुई है। दिनों दिन बढ़ती हुई मंहगाई और बेरोजगार का भी प्रभाव बढ़ रहा है साथ ही बेरोजगार के कारण आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ रही है जो विकास की बाधा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जहां एक ओर आर्थिक एवं सामाजिक विकास आवश्यक है तो दूसरी ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है। जिले में उपजाऊ भूमि रोजगार, उद्योग धन्धे, खनिज सम्पदा, जल विद्युत शक्ति के संसाधन इत्यादि की सीमित उपलब्धता होने और बढ़ती आबादी के कारण ग्रामीण विकास की आवधारणा को और अर्थिक समस्या मूलक बना दिया है। इसी सन्दर्भ में शोधकर्ता द्वारा शोधकार्य के लिए सतना जिले का चयन कर मौलिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अतएव किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ग्रामीण अंचलों के विकास में योगदान के अवदानों को जानने की जिज्ञासा ने उसे एकीकृत ग्रामीण विकास की वास्तविकता का आकलन सामाजिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से करने हेतु प्रयोजन को रूप में अपने शोध आलेख का विषय सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का अवधारणात्मक अध्ययन करना रहा है, ताकि वास्तविकता का मूल्यांकन कर इसकी खूबियों को समाज के सामने सुस्पष्ट किया गया है।

सतना जिले के एकीकृत ग्रामीण विकास के स्तर के नवीन पथों को उजागर किया गया है। विकास प्रक्रिया में ग्रामीण विकास का महत्व वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक माना जा रहा है। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण है। ग्रामीण विकास में जनता की रूचि बहुत तेजी से बढ़ रही है और विकास कार्यक्रमों में व्यक्तियों की बढ़ती हुई भागीदारी योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। प्रारम्भ में विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया था। पश्चात् में यह समझने पर त्वरित विकास केवल तभी सम्भव है जब सरकारी प्रयासों के साथ–साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर व्यक्तियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित है।

एकीकृत ग्रामीण विकास एक बहुतआयामी अवधारणा है, जिसके अन्तर्गत अनेक कार्यक्रमों– कृषि, वानिकी, पशु–पालन, ग्रामीण हस्तशिल्प कला व उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों की मूल संरचना में परिवर्तन इत्यादि का व्यापक स्तर बदलाव सुनिश्चित होता है, जिसकी वजह से ग्रामीण अंचलों में निवासरत व्यक्तियों के पर्यावरणीय, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक औद्योगिक एवं संरचनात्मक बदलाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जिससे ग्रामीण लोगों का जीवन भी समुन्नत होने लगता है और उनका भी योगदान क्षेत्र या राज्य या देश के विकास में सकारात्मक रूप में होने लगता है। सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिसकी वजह से यहां के ग्राम पंचायतों का चतुर्दिक विकास सम्भव हो रहा है। अतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिले की अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की वास्तविक दशाओं का व्यापक रूप में अध्ययन कर शोध क्षेत्र की गतिविधियों पर सूक्ष्म स्तर पर प्रकाश डालना सम्भव हो सका है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के पर्यावरणीय, भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक विकास की खामियों व खूबियों पर प्रकाश डालना समीचीन हो सका है। सतना जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का अवधारणात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, सड़क, पेयजल और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न पहलुओं पर समन्वित रूप से कार्य किया जाता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों का समुचित उपयोग तथा स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास की गति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से न केवल ग्रामीण जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भरता और सतत् विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ –

1. खॉन, चाँद – मध्यप्रदेश के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.), वर्ष 1994
2. विश्वनाथ, टी.आर. – ग्रामीण विकास : नीति एवं प्रशासन, नटराज पब्लिशर्स, देहरादून, वर्ष 2016
3. सिंह, हरी – मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परीक्षण, अप्रकाशित शोध प्रबंध, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.), वर्ष 2005
4. श्रीवास्तव, एम.पी. – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, वर्ष 2018
5. राय, डॉ. रमेन्दु – शोध प्रविधि, न्यू ऐज इन्टरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, वर्ष 2022,
6. शर्मा, जैन पारीक – शोध प्रणाली एवं सांख्यिकीय तकनीकें, रमेश बुक डिपो, जयपुर (राजस्थान), वर्ष 2008